



नागरकिता संशोधन अधनियम (CAA), 2019

प्रलिमिस के लिये:

नागरकिता संशोधन अधनियम (CAA) 2019, 1985 का असम समझौता, नागरकिंग का राष्ट्रीय रजस्टर (NRC)

मेन्स के लिये:

सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, धरमनियेक्षता, संवधान की छठी अनुसूची

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 2020-21 के लिये अपनी नवीनतम वार्षिक रपोर्ट में कहा है कि [नागरकिता संशोधन अधनियम, 2019](#) एक सहानुभूतिपूर्ण और सुधारात्मक कानून है और यह कसी भी भारतीय को नागरकिता से बंचति नहीं करता है।

- CAA का उद्देश्य अफगानसितान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरकिता देना है। यह 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित किया गया और 10 जनवरी, 2020 को लागू हुआ था।
- इस कानून का पूरे देश में व्यापक विरोध हुआ था।

CAA की चुनौतियाँ:

- **विशेष लक्षण समुदाय:** ऐसी आशंकाएँ हैं कि CAA के बाद [राष्ट्रीय नागरकि रजस्टर \(NRC\)](#) का देशव्यापी संकलन किया जाएगा, जिसमें प्रस्तावित नागरकि रजस्टर से बहिष्कृत गैर-मुसलमान लाभान्वति होंगे, जबकि बहिष्कृत मुसलमानों को अपनी नागरकिता साबित करनी होगी।
- **उत्तर-पूर्व से संबंधित मुद्दे:** यह 1985 के असम समझौते का खंडन करता है, जिसमें कहा गया है कि 25 मार्च, 1971 के बाद बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों, चाहे वे कसी भी धरम के हों, को नियोजित कर दिया जाएगा।
 - असम में अनुमानित 20 मलियन अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं और ये प्रवासी राज्य के संसाधनों और अरथव्यवस्था पर दबाव डालने के अलावा राज्य की जनसांख्यिकी को अनविरल्य रूप से परविरत्ति करते हैं।
- **मौलिक अधिकारों के खलिफ़:** अलोचकों का तर्क है कि यह संवधान के [अनुच्छेद 14](#) (समानता के अधिकार की गारंटी देता है जो नागरकिंग और विदेशियों दोनों पर लागू होता है) तथा संवधान की प्रस्तावना में नहिं धरमनियेक्षता के संदिधांत का उल्लंघन है।
- **भेदभावपूर्ण:** भारत में कई अन्य शरणारथी हैं जिनमें श्रीलंका के तमिल और मध्यांमार के हिंदू राहगिया शामिल हैं। ये अधनियम के दायरे में नहीं आते हैं।
- **प्रशासन में कठनाई:** सरकार के लिये अवैध प्रवासियों और सताए गए लोगों के बीच अंतर करना मुश्किल होगा।
- **दवापिक्षीय संबंधों में बाधा:** यह अधनियम उपर्युक्त तीन देशों में धार्मिक उत्पीड़न पर प्रकाश डालता है और इस प्रकार उनके साथ हमारे दवापिक्षीय संबंधों को खराब कर सकता है।

गृह मंत्रालय द्वारा स्पष्टीकरण:

- **भारतीय नागरकिंग पर लागू नहीं:** CAA भारतीय नागरकिंग पर लागू नहीं होता है। इसलिये यह कसी भी तरह से कसी भी भारतीय नागरकि के अधिकार को समाप्त या कम नहीं करता है।
- **भारतीय नागरकिता प्राप्त करने की कानूनी प्रक्रिया अपरविरत्ति रहती है:**
- इसके अलावा [नागरकिता अधनियम, 1955](#) में प्रदान की गई कसी भी शरेणी के कसी विदेशी द्वारा भारतीय नागरकिता प्राप्त करने की वर्तमान कानूनी प्रक्रिया परिवालन में है और CAA इस कानूनी स्थिति में कसी भी तरह से संशोधन या परविरत्ति नहीं करता है।
 - अतः कसी भी देश के कसी भी धरम के कानूनी प्रवासियों के पंजीकरण या देशीयकरण के लिये कानून में पहले से प्रदान की गई पात्रता शर्तों को पूरा करने के बाद ही भारतीय नागरकिता प्राप्त की जा सकेगी।
- **पूर्वोत्तर भारत से संबंधित मुद्दों को सुलझाना:** वार्षिक रपोर्ट में एक बार फिर पूर्वोत्तर में कानून को लेकर आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है जिसमें कहा गया है कि [संवधान की छठी अनुसूची](#) के तहत कृष्णत्रै और [इन लाइन परमिट](#) शासन के तहत आने वाले कृष्णत्रै को शामिल

करने से क्षेत्र की स्वदेशी और आदविसी आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

आगे की राह

- इसके बारे में नियमों की अधिसूचना, जिसके बनि कानून लागू नहीं किया जा सकता है, सरकार की ओर से कोई प्रतिबिधिता न होने के कारण लंबति है।
- इस प्रकार गृह मंत्रालय को चाहिए कि वह CAA नियमों को अत्यंत पारदर्शिता के साथ अधिसूचित करे तथा इससे जुड़ी आशंकाओं को दूर करे।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न: भारतीय संविधान में पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची के प्रावधान संबंधित हैं: (2015)

- (a) अनुसूचित जनजातियों के हतियों की रक्षा करना
- (b) राज्यों के बीच की सीमाओं का नियंत्रण
- (c) पंचायतों की ज़मीमेदारी, शक्तियों, अधिकार का नियंत्रण
- (d) सभी सीमावर्ती राज्यों के हतियों की रक्षा करना

उत्तर: (a)

- पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिये प्रावधान करती है।
- छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/mha-on-citizenship-amendment-act-2019>